विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

वर्ष 38 अंक 343
पृष्ठ 32+12+4=48+8 (टैब)
लखनऊ, शनिवार
7 अक्टूबर 2017
नगर संस्करण

निर्यातक बोले, जीएसटी से अटका निर्यात, पाक को मिल रहे हैं ऑर्डर

ई-वे बिल व सब्सीडियरी कंपनियों के मामले सुलझाने का किया आग्रह

राब्यू, लखनऊ : जीएसटी लागू होने के बाद निर्यात से जुड़े यूपी के जिन उद्योगों को बड़ा झटका लगा, उसमें कॉटन इंडस्ट्री भी है। असंगठित क्षेत्र के जिन बुनकरों से माल आता है, उनका जीएसटी में पंजीकरण नहीं है इसलिए धागे पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी नहीं है। इससे सूबे का सूती माल 18% महंगा हुआ व इससे एक्सपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर अब पाकिस्तान की झोली में गिरने लगे हैं।

प्रदेश के निर्यातकों ने कुछ ऐसी ही समस्याएं शुक्रवार को उप्र, उत्तराखंड, बिहार व झारखंड के मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त शिव नारायण सिंह के सामने रखीं। एसोचेम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ के सूती निर्यातक विनीत गुप्ता ने बताया कि पहले वैट में 18 फीसद टैक्स लगने के बाद भी घालमेल की वजह से कीमतों पर इसका असर नहीं पड़ता था, लेकिन अब यही टैक्स आड़े आ रहा है। मुख्य आयुक्त सिंह ने भी इस पर माना कि पहले 90 फीसद चीजें छिपी हुई थीं, जो अब सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि सूती उद्योग में गुजरात में भी इसी तरह की समस्या आ रही है, जबकि कई जगह कोयला कारोबारियों को पिछली गड़बड़ व्यवस्था के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विनीत गुप्ता ने बताया कि जीएसटी से निर्यात पर असर पड़ने से बुनकरों का भी रोजगार छिन रहा है। कई बुनकर पुश्तैनी पेशा छोड़कर ई-रिक्शा चलाने लगे हैं। कारपोरेट लॉयर आरके पोरवाल ने होल्डिंग कंपनी के साथ सब्सीडियरी कंपनी में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी प्रक्रिया दोहराए जाने को संसाधनों का दुरुपयोग बताया।

निर्यातकों के साथ आयोजित सवांद कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क शिव नारायण सिंह

इकोनॉमी है मुर्गी, टैक्स अंडा

'लोहे का स्वाद लोहार से नहीं घोड़े से पूछो, जिसके मुंह में लगाम है।' धूमिल की इस कविता का हवाला देते हुए मुख्य आयुक्त शिव नारायण सिंह ने कहा कि जीएसटी का असर वास्तव में कारोबारियों से ही पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था मुर्गी है और टैक्स अंडा। मुर्गी स्वस्थ रहेगी, कारोबार बढ़ेगा, तब ही टैक्स का अंडा मिलेगा। कविता के साथ पेंटिंग का भी शौक रखने वाले मुख्य आयुक्त ने कहा कि जीएसटी ऑयल पेंटिंग की तरह है, जिसमें आखिरी समय तक बदलाव किए जाने की संभावना है। मुख्य आयुक्त ने कहा कि जीएसटी की समस्याएं दूर होने में अभी एक साल लगेगा।

नहीं मिला जून तक का क्रेडिट

एसोचेम यूपी की कर समिति के अध्यक्ष एके गुप्ता ने जीएसटी में ट्रांजीशनल क्रेडिट की समस्या उठाते हुए कहा कि शायद ही किसी को यह अब तक मिल पाया हो। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि एक साल में जीएसटी भी आयकर की तरह सरल हो जाएगा। एसोचेम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय आचार्य ने जीएसटी की समस्याओं पर सरकार के रुख को संवेदनशील बताया।

ई-हेल्पलाइन पर बताएं समस्याएं

सीमा शुल्क आयुक्त शिव कुमार शर्मा ने निर्यातकों को बताया कि आयात-निर्यात या जीएसटी से जुड़ी कोई भी समस्या वह कस्टम्स लखनऊ की वेबसाइट पर दिए गए ई-हेल्पलाइन के लिंक पर बता सकते हैं। शर्मा ने 72 घंटे में इस हेल्पलाइन से समाधान का दावा किया है।

योगी को अप्रैल में चेताया था

मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त शिव नारायण सिंह ने दावा किया कि जीएसटी में अब सामने आ रही समस्याओं को लेकर उन्होंने अप्रैल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बता दिया था। केंद्र व राज्य की एजेंसियों में तालमेल बनाने को उन्होंने सबसे बड़ी समस्या ठहराते हुए कहा कि इसकी आशंका पहले से थी।